समक्ष पी.सी जैन, ए.सी.जे, सुरिंदर सिंह & आई.एस.तीवाना माननीय न्यायमूर्ति।

पी.पी.कपूर सुपरिंटेंडेंट और अन्य – *अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य – प्रतिवादी

1983 की सिविल व्रिट याचिका नंबर 4**848**

30 अगस्त 1984

भारत का संविधान ***1950***-अनुच्छेद ***16*** और ***309***-पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग ***III)*** नियम***, 1952***-नियम ***6***-सहायक के पदों पर क्लर्कों की पदोन्नति-कार्यकारी निर्देशों द्वारा ऐसी पदोन्नति के लिए निर्धारित परीक्षण-न्यायालय द्वारा निर्देशों को अमान्य घोषित किया गया वरिष्ठता और परिणामी पदोन्नति का लाभ केवल डिक्री धारकों को देने का सरकार का निर्णय - इसके बाद न्यायालय न जाने वाले कर्मचारियों को भी लाभ देने का निर्णय - क्या वैध - परीक्षण के आधार पर पदोन्नति पाने वालों का प्रत्यावर्तन - क्या कहा जा सकता है कठिनाई पैदा करना।

अभिनिर्णित, कि जब न्यायालय द्वारा निर्देशों को अमान्य घोषित करने का निर्णय आया था तो राज्य सरकार को कानूनी तौर पर नहीं बल्कि उस निर्णय का लाभ उन सभी अधिकारियों को देना चाहिए था जिनकी पदोन्नति पर निर्देशों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। राज्य सरकार ने बिना अपना दिमाग लगाए केवल उन लोगों को फैसले का लाभ देने के निर्देश जारी किए जो अदालत गए थे और बाद में मामले पर पुनर्विचार करने का फैसला किया। इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने का निर्णय लेने में सरकार की ओर से कुछ भी गलत या अवैध प्रतीत नहीं होता है। सरकार ने फैसले को लागू न करने को लेकर पहले कोई सुविचारित सचेत निर्णय नहीं दिया था. यदि सरकार ने उस समय अपना दिमाग लगाया होता तो निश्चित रूप से उसने अदालत के फैसले

का पालन करने का फैसला किया होता और जो लोग अदालत में गए थे उन तक इसकी प्रयोज्यता को सीमित करके इसे नजरअंदाज नहीं किया होता। हालाँकि न्यायालय का निर्णय केवल कुछ अधिकारियों के मामले में ही सुनाया गया था, फिर भी निर्णय का अनुपात यह है कि पदोन्नति के लिए परीक्षण निर्धारित करने वाले निर्देश कानूनी रूप से जारी नहीं किए जा सके। यह समझ में नहीं आता कि उस फैसले का प्रयोग केवल उन अधिकारियों तक कैसे सीमित हो सकता है जो अदालत गए थे। उस समय राज्य सरकार से अपेक्षा थी कि वह उन अधिकारियों के संबंध में भी फैसले को लागू करती जो अदालत नहीं गये थे. हालाँकि, सरकार ने बाद के निर्देश जारी किए हैं, और अदालतों को राज्य सरकार द्वारा पहले ही की गई गलती को बाद के निर्देशों को रद्द करके जारी रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिन अधिकारियों को टेस्ट के आधार पर पदोन्नत किया गया था, वे उन अधिकारियों से अधिक व्यथित कैसे महसूस कर सकते हैं, जिनका प्रमोशन का अधिकार उस टेस्ट के नुस्खे के परिणामस्वरूप छीन लिया गया था, जिसे अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था।

(पैरा 10 और 11)

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका है जिसमें प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहतें दी जाएं: -

(ए) सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की जाए जिसमें विवादित निर्देश अनुलग्नक पी.4 से संबंधित उत्तरदाताओं के रिकॉर्ड मांगे जाएं और उसके अवलोकन के बाद विवादित निर्देश अनुलग्नक पी.4 को रद्द कर दिया जाए।

(बी) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझे, जारी किया जाएगा।

(सी) एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी को इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक विवादित निर्देशों के अनुसरण में कोई और कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए।

(डी) याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को पूर्व सूचना देने से छूट दी जाए।

(ई) अनुबंध पी. 1 से पी. 4 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जा सकती है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

(एफ) याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

याचिकाकर्ताओं के लिए कुलदीप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और जी.सी. गुप्ता, अधिवक्ता।

हरभगवान सिंह, ए.जी., हरियाणा, निर्मल यादव के साथ।

एम. आर. अग्निहोत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. एस. दोआबिया, अधिवक्ता के साथ, अतिरिक्त ए.ए.जी.एच प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

प्रेम चंद जैन, ए.सी.जे

(1) हमारा यह निर्णय इस याचिका और 1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 5238 और 5460 और 1984 की 140 का निपटारा कर देगा क्योंकि इन सभी याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं।

(2) विवाद की सराहना करने के लिए, याचिका की कुछ मुख्य विशेषताएं बताई जा सकती हैं।

(3) याचिकाकर्ता वर्ष 1945 और 1958 के बीच समग्र पंजाब सिविल सचिवालय में क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल हुए। पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर उन्हें हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया था। पंजाब में पुनर्गठन से पहले, 21 जून, 1958 को सरकार द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी किए गए थे कि सिविल सचिवालय में सहायक के पदों पर सभी पदोन्नतियां निर्धारित

परीक्षा के आधार पर की जाएंगी। इन निर्देशों के परिणामस्वरूप, जो मौलवी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ थे, उन्हें सहायक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया और जिन्हें अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया, उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता के आधार पर वापस कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित परीक्षा में विधिवत अर्हता प्राप्त की थी और उन्हें याचिका के साथ अनुबंध पी. 1 के रूप में संलग्न चार्ट में उल्लिखित तिथियों पर सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जो क्लर्क परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ थे, चाहे वे वरिष्ठ हों या कनिष्ठ।' याचिकाकर्ताओं के लिए, क्लर्कों के संवर्ग में या जिन्होंने बाद में परीक्षा उत्तीर्ण की, वे सहायकों के संवर्ग में याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ हो गए।

(4) याचिका में कहा गया है कि कुछ क्लर्क जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के कारण कनिष्ठ बन गए थे, उन्होंने कार्यकारी निर्देशों की वैधता को चुनौती देते हुए नागरिक मुकदमे दायर किए। अंततः उन मुकदमों पर फैसला सुनाया गया। इस मामले को हरियाणा राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में उठाया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हरियाणा राज्य और अन्य बनाम शमशेर जंग शुक्ला और अन्य के मामले में, यह माना गया कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है और लागू निर्देशों के अनुसार पंजाब सिविल सचिवालय के नियम 6 में संशोधन किया गया है। (राज्य सेवा वर्ग III) नियम, 1952, को रद्द कर दिया गया। शमशेर जंग शुक्ला के मामले (सुप्रा) में निर्णय के परिणामस्वरूप चयन के विषय पर एक परिपत्र पत्र संख्या 5901-4-जीएस-द्वितीय 73/23071, दिनांक 11 सितंबर, 1973, सभी विभागाध्यक्षों को संबोधित किया गया था। सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए लिपिकों की एक परीक्षा के माध्यम से कहा जाएगा:-

“यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जाए। अब यह निर्णय लिया गया है कि इसका लाभ केवल उन्हीं अधिकारियों को दिया जाए जो न्यायालय में गए और अपने पक्ष में डिक्री करा ली। तदनुसार, उन्हें उचित

वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसे कि वर्ष 1958 में सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में उनके मामलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त परिपत्र पत्र से व्यथित होकर हरियाणा सचिवालय, चंडीगढ़ के कुछ सहायकों ने इसकी वैधता को चुनौती देते हुए 1973 की सिविल रिट याचिका संख्या 3314 दायर की। हरियाणा राज्य ने रिट याचिका का गुण-दोष के साथ-साथ इस आधार पर भी विरोध किया कि याचिका में खामियां हैं। उस रिट याचिका को एम. आर. शर्मा जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) द्वारा 17 नवंबर, 1975 को पूरी तरह से लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया गया था, और फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील (1976 का एल.पी.ए. संख्या 19) को भी खारिज कर दिया गया था।

(5) यह भी कहा गया है कि शमशेर जंग शुक्ला के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 11 साल से अधिक और सी.डब्ल्यू.पी. की अंतिम बर्खास्तगी के 4 साल से अधिक समय बाद। संख्या 3314/1973, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने दिनांक 1 जून, 1983, अनुलग्नक पी. 4 पर नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अपने निर्णय के लिए कोई कारण बताए बिना, यह कहा गया है कि सरकार ने इस पर दोबारा विचार किया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की और अब निर्णय लिया है कि जहां भी आवश्यक हो, सभी विभाग आगामी पैराग्राफों में बताए गए कदम उठा सकते हैं। गिनाए गए चरणों में शामिल हैं:

"4. ऊपर उल्लिखित निर्देश, दिनांक 23 अक्टूबर, 1957 और 5 सितंबर, 1958 और सहायक के रूप में पदोन्नति के संबंध में नीति को विस्तृत करने की दृष्टि से जारी किए गए कोई भी अनुदेश, जिसमें ऊपर संदर्भित दिनांक 11 सितंबर, 1973 का पत्र भी शामिल है। रद्द किया हुआ समझा जाना चाहिए। तदनुसार, इसका लाभ अब सभी अधिकारियों को दिया जाएगा, चाहे वे अदालत में गए हों या नहीं और अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त की हो।

9. पदोन्नति के समायोजन के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं:-

(i) जिन लोगों को पंजाब सरकार के समग्र निर्देश संख्या 9129-सी-56/ में शामिल वरिष्ठता-सह-योग्यता फॉर्मूला के आधार पर, उस तिथि पर सहायक ग्रेड में पदोन्नति के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था, जो अन्यथा पदोन्नति के लिए देय होता। 3964, दिनांक 17 सितंबर, 1956 पर विचार करना होगा और यदि वे उस विशेष तिथि पर उक्त फार्मूले के आधार पर फिट पाए जाते हैं और यदि वे निर्धारित अनुभव की शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनके मामले में पदोन्नति का आदेश जारी किया जाएगा। उन्हें उक्त तिथि पर पदोन्नत माना जाए और तदनुसार उनका वेतन निर्धारित किया जाए।

(ii) जिन्हें सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की नियत तिथि पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन इस शर्त के अधीन कि उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और इस शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर उन्हें वापस कर दिया गया था। , उनके प्रत्यावर्तन को पूर्ववत करना होगा, बेशक, उनकी सेवा के रिकॉर्ड और निर्धारित अनुभव, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक तिथि (वरिष्ठता के आधार पर उन्हें पदोन्नति की तारीख दी जाएगी) पर उनकी फिटनेस के आधार पर, इसी तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए जिनकी पदोन्नति सहायक के पद पर अस्थायी/तदर्थ आधार पर (उनकी वरिष्ठता के अनुसार) की गई थी, हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी। बाद में इस परीक्षा में योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता पर इस धारणा/शर्त पर जारी व्यवस्था को वापस कर दिया जाएगा कि जैसे ही इस परीक्षा में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होंगे, उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

(iii) उपरोक्त आइटम (i) और (ii) में उल्लिखित पदोन्नति के पुन: समायोजन करते समय, स्पष्ट रूप से पदोन्नति की प्रासंगिक तारीखों की गणना उन अधिकारियों की पदोन्नति की तारीखों के आधार पर की जाएगी, जो अपने कनिष्ठ पद की परवाह किए बिना संबंधित वरिष्ठता सूची को

परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नत किया गया था, और पदोन्नति को वरिष्ठता के अनुसार और रिक्तियां उपलब्ध होने के क्रम में समायोजित किया जाएगा, सूची में नीचे जाने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों को उनके तत्काल वरिष्ठ तक के चरण में पदोन्नत किया जाएगा। (क्लर्कों की वरिष्ठता सूची में) को समायोजित किया जाता है और पूर्व की पदोन्नति के लिए एक रिक्ति उपलब्ध होती है।

10. उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की शर्त अमान्य हो गई है और कनिष्ठ अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के कारण पूर्व में हुए अधिक्रमण को अस्थिर कर दिया जाएगा, जब तक कि वे अपनी स्वयं की वरिष्ठता के आधार पर इस बीच सहायक के रूप में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के हकदार नहीं हो जाते।

परिलब्धियों का संरक्षण:

11. उन व्यक्तियों की परिलब्धियाँ जिन्हें उपरोक्त स्थिति में या तो क्लर्क के रूप में वापस जाना है या जो प्रधान सहायक, उप-अधीक्षक, अधीक्षक आदि के उच्च पद पर रहने के लिए बहुत कनिष्ठ हो गए हैं, जैसा भी मामला हो, सुरक्षित रखा जाएगा, यदि ऐसी परिलब्धियाँ निम्नलिखित में से किसी भी मामले में निकाली जाती हैं: -

(i) निर्देश संख्या 4800-जीआईआई-57/21176, दिनांक 23 अक्टूबर, 1957 के संदर्भ में की गई पदोन्नति, जो 22 अक्टूबर, 1970 तक प्रचलित थी, यानी वह तारीख जब संशोधित निर्देश जारी किए गए थे, - परिपत्र पत्र संख्या 8073 के माध्यम से- 2जीएस-70, दिनांक 27 अक्टूबर, 1970। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से की गई पदोन्नति (निर्देशों के बावजूद, दिनांक 27 अक्टूबर, 1980 ऊपर संदर्भित) 10 अप्रैल, 1972 तक, यानी वह तारीख जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया था।

उपरोक्त के शुद्ध परिणाम के रूप में, 19 अप्रैल, 1972 तक निकाली गई परिलब्धियाँ सुरक्षित रहेंगी।

वरिष्ठता:

12. उपरोक्त तर्ज पर पदोन्नति के समायोजन के लिए स्पष्ट रूप से वरिष्ठता सूचियों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता होगी।

निम्नानुसार कार्रवाई की जा सकती है:-

(i) सहायक, प्रधान सहायक, उपाधीक्षक, अधीक्षक आदि संवर्ग में अधिकारियों की वरिष्ठता, जैसा भी मामला हो, लिपिकों के संवर्ग की तरह गहन वरिष्ठता को बहाल करके पुनर्गठित की जानी चाहिए, बशर्ते कि उनकी उपयुक्तता हो। जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 9(i) में बताया गया है, उच्चतर रैंक। यह सहायक ग्रेड परीक्षा से संबंधित निर्देशों के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना किया जा सकता है, जिसे अब उच्च/उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। हालाँकि, उपरोक्त पैरा 11 के संदर्भ में परिलब्धियों के संबंध में सुरक्षा, यदि दी जाती है, तो वरिष्ठता में कोई लाभ नहीं होगा।

(ii) जिन आशुलिपिकों और आशुलिपिकों को लिपिकीय पंक्ति से पदोन्नत होकर अन्य रैंकों पर पदोन्नत किया गया था, उनकी परस्पर वरिष्ठता उस रैंक के समान बनी रहेगी, जहां से उन्हें पदोन्नत किया गया था क्योंकि वरिष्ठ रैंकों में उनकी पदोन्नति हो चुकी है। न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया।

(iii) जिन व्यक्तियों को विभिन्न सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण या सीधी नियुक्ति द्वारा सहायक के रूप में भर्ती किया गया था, उनकी पदोन्नति के मुकाबले उनकी वरिष्ठता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, जिसे सामान्य रूप से संदर्भ के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। निरंतर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक. केवल वरिष्ठता सूची को पुनर्गठित करने से उनके मामले में कोई अधिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वरिष्ठता सूची को पहले तो एक के लिए एक के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए और दूसरे उन व्यक्तियों को सही स्थानों पर लाकर, जिन्हें केवल सहायक

ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करके वरिष्ठता में छलांग लगाकर पदोन्नत किया गया था, फिर से तैयार किया जाएगा।

(iv) पदोन्नत संवर्ग में संशोधित अनंतिम सूचियां विभागों द्वारा संबंधित कर्मचारियों के बीच प्रसारित की जानी चाहिए और उनसे दो महीने की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए।

(v) विभागों को अनंतिम वरिष्ठता सूचियों पर आपत्तियां आमंत्रित करते समय यह स्पष्ट करना चाहिए कि वरिष्ठता सूचियां, जहां भी लागू हो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन होंगी। जहां वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण में उन वरिष्ठता सूचियों में परिवर्तन शामिल है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के संदर्भ में भारत सरकार के परामर्श से तैयार की गई थीं। इस संबंध में भारत सरकार का संदर्भ स्पष्ट तरीके से दिया जाना चाहिए मामले की पूरी पृष्ठभूमि, खासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की।

(vi) हालाँकि, संशोधित अनंतिम वरिष्ठता सूची का संचालन तुरंत शुरू किया जाना चाहिए और भारत सरकार की मंजूरी तक इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

पुष्टि:

(13) पुष्टिकरणों को उपरोक्त पुनर्रचना के अनुसार वरिष्ठता के क्रम में विनियमित किया जाना चाहिए, सबसे पहले पुष्टिकरण की तारीखों के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए अधिकांश सेवा नियमों में मौजूद प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और दूसरी बात यह है कि यह एक प्रमुख सेवा लाभ है जो वरिष्ठता के अनुसार अर्जित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, पद की प्रकृति के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवीक्षा या स्थानापन्न की अवधि के दौरान कर्तव्यों का सफल निष्पादन आवश्यक होगा। परिणामस्वरूप, जो लोग पदोन्नत रैंक में कनिष्ठ हो जाते हैं, उन्हें

यदि उनकी पंक्ति को स्थानांतरित करने के लिए कोई वास्तविक रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें एक अवसर देने के बाद डीकन्फर्म करना होगा, या वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त अतिरिक्त पद सृजित करने होंगे। प्रत्येक विभाग में स्थिति के अनुसार स्थायीकरणों का पुनः समायोजन एवं अतिरिक्त पदों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए।

बाद में उच्च पदों पर पदोन्नति:

(14) बाद में पदोन्नतियां उपरोक्तानुसार पुनर्गठित वरिष्ठता सूचियों के आधार पर की जा सकती हैं, जो निश्चित रूप से अन्य नियमों के अधीन होंगी, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए अलग से बनाया जा सकता है। सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप बनाई गई वरिष्ठता के आधार पर अब तक पदोन्नत किए गए लोगों को वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए उच्च रैंक में स्थान खाली करना होगा और रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही उनकी बारी के अनुसार समायोजित किया जाएगा। चूंकि उपरोक्त निर्देशों ने याचिकाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, इसलिए वर्तमान और अन्य संबंधित रिट याचिकाएं 1 जून, 1983 के निर्देशों की वैधता और वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, याचिका में अनुलग्नक पी. 4 की प्रति संलग्न करें। याचिका के पैराग्राफ 14 में बताए गए आधार। यह रिट याचिका 14 अक्टूबर, 1983 को प्रस्ताव सुनवाई के लिए आई। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुनने के बाद, खंडपीठ ने महाधिवक्ता, हरियाणा को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया।

(6) याचिकाकर्ताओं ने केवल राज्य को एक पक्ष बनाया था। चूंकि रिट याचिका के निर्णय से कुछ निजी व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना थी, इसलिए सर्वश्री जे.आर. वोहरा, तिलक राज शर्मा, सी.एल. आनंद, आई.सी. कटारिया, के.बी. कपूर, के.एस. बिंद्रा और मुक्त बिहारी लाई द्वारा 1983 का सिविल विविध आवेदन संख्या 2973 दायर किया गया था। स्वयं को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने के लिए। उस आवेदन की अनुमति दी गई थी और, दिनांक 15 दिसंबर, 1983 के आदेश के तहत, आवेदकों को

प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं, एक राज्य की ओर से और दूसरा निजी उत्तरदाताओं की ओर से, जिसमें याचिका में लगाए गए भौतिक आरोपों का खंडन किया गया है।

(7) राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में, मुख्य रुख यह है कि विवादित निर्देश केवल शमशेर जंग शुक्ला के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जारी किए गए हैं और निर्देश पूरी तरह से कानूनी और वैध हैं। लिखित बयान दाखिल करने के बाद, मोशन बेंच ने अंततः 16 जनवरी, 1964 को मामले की सुनवाई की। चूंकि याचिका में शामिल बिंदु कुछ महत्वपूर्ण था, इसलिए याचिका स्वीकार कर ली गई और पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई करने का आदेश दिया गया। विवादित निर्देशों के परिणामस्वरूप होने वाले प्रत्यावर्तन पर भी रोक लगा दी गई। इस तरह हम मामले को समझ गए हैं।

(8) इससे पहले कि मैं विवाद के गुणों पर चर्चा करूं, मैं थोड़ा इतिहास तलाशने का प्रस्ताव करता हूं कि विवादित निर्देश कैसे अस्तित्व में आए। जैसा कि फैसले के पहले भाग में आया है, शमशेर जंग शुक्ला के मामले में पदोन्नति के लिए एक परीक्षा निर्धारित करने वाले 21 जून, 1968 के निर्देशों को अंततः रद्द कर दिया गया था, जिसका फैसला 19 अप्रैल, 1971 को हुआ था। सितंबर, 1973 में मामले पर विचार करने पर हरियाणा राज्य ने उस निर्णय का लाभ सभी अधिकारियों को न देकर केवल उन अधिकारियों को देने का निर्णय लिया जो न्यायालय गए थे और अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त कर ली थी। हरियाणा राज्य के इन निर्देशों के कारण कुछ पीड़ित अधिकारियों द्वारा फिर से याचिका दायर करना आवश्यक हो गया, लेकिन उनकी रिट याचिका केवल खामियों के आधार पर विफल हो गई। हरियाणा राज्य के विपरीत, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1976 में उन सभी अधिकारियों को वरिष्ठता का लाभ देने के निर्देश जारी किए थे जिनकी वरिष्ठता सहायक ग्रेड परीक्षा की शुरूआत के परिणामस्वरूप प्रभावित हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि जिन पीड़ित अधिकारियों को हटा दिया गया था, उनके कई अभ्यावेदन उनकी मूल वरिष्ठता की बहाली

के लिए प्रार्थना करते हुए दायर किए गए थे। मामले की उच्चतम स्तर पर जांच की गयी. 16 अगस्त, 1977 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए एक समान पैटर्न अपनाया जाए। यह भी इच्छा व्यक्त की गई कि मुख्य सचिव, हरियाणा, पंजाब के मुख्य सचिव के साथ चर्चा करें और पता लगाएं कि दोनों राज्यों द्वारा समान तर्ज पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है। अक्टूबर, 1977 में मुख्य सचिव, हरियाणा ने इस मामले पर पंजाब के मुख्य सचिव के साथ दो बार चर्चा की। ऐसा लग रहा है कि दोनों मुख्य सचिवों के बीच कोई फैसला नहीं हो सका. 22 जून, 1978 को, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा ने पाया कि पंजाब सरकार ने जनवरी, 1976 में निर्देश जारी किए थे और उन निर्देशों के आधार पर पंजाब सिविल सचिवालय के कर्मचारियों की एक अनंतिम वरिष्ठता सूची पंजाब सरकार द्वारा प्रसारित की गई थी। 24 फरवरी, 1977 को, और हरियाणा सरकार द्वारा इसी तरह का निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका। बाद में, 1 अगस्त, 1978 को, मुख्य सचिव, हरियाणा ने सुझाव दिया कि मामले की जांच के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए, लेकिन मुख्यमंत्री, हरियाणा, इस सुझाव से सहमत नहीं थे और चाहते थे कि मामले की जांच की जानी चाहिए। पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मद्देनजर. तदनुसार, पंजाब सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा मामले की जांच की गई। 8 नवंबर, 1978 को, मुख्य सचिव, हरियाणा ने फिर से यह जानना चाहा कि क्या पंजाब सरकार ने इस मामले में अंतिम निर्णय लिया है और उन्हें सूचित किया गया कि जनवरी, 1976 में बहाल करने के लिए जारी किए गए पंजाब सरकार के आदेशों को लागू करने का फिल्मी निर्णय लिया गया है। गैर याचिकाकर्ताओं सहित कर्मचारियों की वरिष्ठता पर तब तक ध्यान नहीं दिया गया था और पंजाब सरकार द्वारा इस मामले पर दोबारा विचार करने की संभावना थी। 2 दिसंबर, 1978 को मुख्यमंत्री, हरियाणा ने कहा कि उनकी राय में यह कोई मायने नहीं रखता कि पंजाब सरकार ने 1976 में जारी निर्देशों को लागू किया है या नहीं और हरियाणा सरकार को भी इन्हें पूरा करने

के बाद पंजाब सरकार की तर्ज पर निर्देश जारी करने चाहिए। आवश्यक औपचारिकताएँ. हालाँकि, पुनर्विचार करने पर और दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों के अभ्यावेदन को सुनने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति ने व्यावहारिक रूप से चार साल की अवधि ली और जून, 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि यह अनुचित होगा यदि उन सहायकों की वरिष्ठता, जो लंबे समय से सहायक ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप पदोन्नत हुए हैं। इस अंतिम चरण में परेशान होने से उनके नुकसान और उन लोगों के पक्ष में, जिनके पास कोई कानूनी दावा नहीं है, हालांकि यह केवल लापरवाही के कारण हो सकता है। हालाँकि हो सकता है कि लैचेस कुछ व्यक्तियों को राहत देने के रास्ते में न आया हो; यदि इसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तो इसकी छूट उचित नहीं होगी। हालाँकि, उन लोगों को होने वाली कठिनाई को आंशिक रूप से कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे, जिन्होंने मूल रूप से अपने लिए कानूनी उपचार का सहारा नहीं लिया था और बाद में केवल अनुग्रह उपाय के रूप में सीमा से प्रभावित हुए थे।समिति की इस सिफ़ारिश की सरकार ने जांच की और 1 जून, 1983 को यह निर्णय लिया गया कि अधिकारियों की वरिष्ठता बहाल करने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में सरकार को पंजाब सरकार के अनुरूप काम करना चाहिए। सहायक ग्रेड परीक्षा की शुरूआत के परिणामस्वरूप प्रतिस्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में, हरियाणा राज्य ने इन निर्देशों के माध्यम से उन अधिकारियों को भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने न्यायालय से कोई डिक्री प्राप्त नहीं की थी। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा आक्षेपित निर्देश जारी किये गये हैं।

(9) आक्षेपित निर्देशों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का मुख्य हमला यह था कि सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा 1973 में ही एक सचेत निर्णय लिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ दिया जाना चाहिए। केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त की थी और इस तरह के निर्णय की कानूनी तौर

पर उसी तर्क के आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती थी जिसे वर्ष 1973 में निर्देश जारी करने के समय स्वीकार नहीं किया गया था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों की वरिष्ठता तय कर दी गई थी और परिणामी पदोन्नति भी कर दी गई थी और यदि लगाए गए निर्देशों को कायम रखा जाता है और इसके आधार पर नई वरिष्ठता सूची बनाई जाती है तो इससे याचिकाकर्ताओं को गंभीर कठिनाई होगी। तैयार है। दूसरी ओर, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री हरभगवान सिंह ने तर्क दिया कि हरियाणा राज्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है; वर्ष 1973 में जारी किए गए पहले के निर्देश राज्य सरकार के लिए लागू निर्देश जारी करने की राह में बाधा नहीं बन सकते थे; राज्य सरकार को अपने पहले के प्रशासनिक निर्देशों की समीक्षा करने का अधिकार है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उन अधिकारियों को बड़ी कठिनाई हुई है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लाभ नहीं मिला है और मामला विचाराधीन है। वर्ष 1977 से राज्य सरकार और अपने निर्णय को सही करने और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने में सरकार की ओर से कोई भी अस्पष्ट देरी नहीं हुई है। विद्वान महाधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि जो याचिकाकर्ता वर्ष 1958 में जारी निर्देशों के अलावा पदोन्नति के हकदार नहीं थे, उन्हें उस लाभ को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उन्हें अवैध रूप से दिया गया था। विद्वान महाधिवक्ता ने अपने तर्क का समर्थन किया यह तर्क देते हुए कि यदि राज्य सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर रही थी, तो देरी का सवाल बाधा नहीं होना चाहिए और न ही यह तथ्य कार्यकारी निर्देशों को अवैध और अमान्य घोषित करने का आधार होना चाहिए।

(10) मामले की परिस्थितियों में सभी मामलों पर गहन विचार करने के बाद, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता लागू निर्देशों को रद्द करने के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहे हैं। हालाँकि दोनों पक्षों की ओर से बार में कुछ न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया था, लेकिन वे मामले की परिस्थितियों में, विवाद पर निर्णय लेने के लिए शायद ही प्रासंगिक हों।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब शमशेर जंग शुक्ला के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो राज्य सरकार को कानूनी तौर पर उस फैसले का लाभ उन सभी अधिकारियों को देना चाहिए था, जिनकी पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। वर्ष 1958 में जारी अनुदेशों द्वारा। राज्य सरकार ने उन कारणों से, जो उसे सबसे अच्छी तरह ज्ञात हैं, यद्यपि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मन की अनुपयुक्तता का मामला था, इसका लाभ देने के लिए वर्ष 1973 में निर्देश जारी किये थे। फैसला केवल उन लोगों के लिए जो कानून की अदालत में गए थे; लेकिन यह पाते हुए कि पंजाब सरकार ने उन सभी अधिकारियों को वरिष्ठता का लाभ देने के निर्देश जारी किए थे जिनकी वरिष्ठता प्रभावित हुई थी, हरियाणा राज्य ने इस मामले पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया। मेरे विचार में, इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्णय लेने में सरकार की ओर से कुछ भी गलत या अवैध प्रतीत नहीं होता है, खासकर जब पंजाब राज्य ने फैसले के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए थे। फिर, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सचिवालय में लालफीताशाही के परिणामस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री की इच्छा अधूरी रह गई। हालांकि 1978 में नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने में पूरे चार साल लग गए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि इस देरी के परिणामस्वरूप उन गरीब अधिकारियों को बड़ी कठिनाई होगी जो हर समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह सही है कि समिति ने निर्देशों में किसी बदलाव की सिफ़ारिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि समिति द्वारा कोई उचित कारण नहीं दिया गया है और केवल 1973 में जारी निर्देशों पर कायम रहने में देरी के सवाल पर समिति विचार कर रही है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील से सहमत हैं कि शमशेर जंग शुक्ला के मामले (सुप्रा) में फैसले को लागू नहीं करने के लिए वर्ष 1973 में कोई भी सुविचारित, सचेत निर्णय लिया गया था। बल्कि तथ्य यह प्रतीत होता है कि लापरवाही से और बिना सोचे-समझे, केवल उन अधिकारियों के संबंध में निर्णय लागू करने के निर्देश जारी किए गए जो कानून की अदालत में गए थे। यदि सरकार ने उस समय अपना दिमाग

लगाया होता, तो निश्चित रूप से उसने देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का पालन करने का फैसला किया होता और जो लोग कानून की अदालत में गए थे, उन तक इसकी प्रयोज्यता को सीमित करके इसे नजरअंदाज नहीं किया होता। यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल कुछ अधिकारियों के मामले में ही दिया गया था, लेकिन उस निर्णय का अनुपात यह है कि पदोन्नति के लिए परीक्षा निर्धारित करने वाले वर्ष 1958 में लागू निर्देश कानूनी रूप से जारी नहीं किए जा सके। मैं यह समझने में असफल हूं कि उस निर्णय का प्रयोग केवल उन अधिकारियों तक कैसे सीमित हो सकता है जो न्यायालय गए थे। उस समय राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह उन अधिकारियों के संबंध में भी निर्णय लागू करेगी जो कानून की अदालत में नहीं गए थे। हालाँकि, चूँकि सरकार अब बेहतर समझ में आ गई है, इसलिए अदालतों को निर्देशों को रद्द करके राज्य सरकार द्वारा पहले ही की गई गलती को बरकरार नहीं रखना चाहिए। यह देखना उचित है कि राज्य सरकारें न्यायिक निर्णयों का पालन करें और उन्हें किसी न किसी तकनीकी बहाने से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है।

(11) जहां तक अन्याय का सवाल है, मैं फिर से यह समझने में असफल रहा कि याचिकाकर्ता उन अधिकारियों से कैसे अधिक व्यथित हैं जिनकी पदोन्नति का अधिकार उस परीक्षा के नुस्खे के परिणामस्वरूप छीन लिया गया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। . यदि वह परीक्षण निर्धारित नहीं किया गया होता, तो निजी उत्तरदाता और समान स्थिति वाले अन्य व्यक्ति याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ माने जाते। यदि याचिकाकर्ताओं को उन आक्षेपित निर्देशों के परिणामस्वरूप निजी उत्तरदाताओं की तुलना में भविष्य में पदोन्नति के अवसर से वंचित किया जाता है, जो केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी बना रहे हैं, तो उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि विवादित निर्देश वैध हैं और उनमें कोई कानूनी खामियां नहीं हैं।

(12) विवादित निर्देशों की वैधता पर राय रखने के बाद, मामला अब गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए एकल पीठ के समक्ष जाएगा।

सुरिंदर सिंह, जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा